कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

संख्याः– 175 /30 एम0एम0सी0/2023–24 दिनांकः 21/05/2024

सेवा में,

रजिस्ट्रार
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय :– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–440/2023 नवीन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 18.03.2024 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, झाँसी की ओर से आख्या/अनुदेश प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–440/2023 नवीन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में विचाराधीन है। उक्त वाद में उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिवादी संख्या–1,4,7,8 व 10 क्रमशः मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी, झाँसी, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी तथा वनाधिकारी, झाँसी वन प्रभाग, झाँसी में पारित आदेश दिनांकः 18.03.2024 के अनुपालन में आख्या/अनुदेश आवश्यक कार्यवाही एवं सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/
प्रभारी अधिकारी (खनिज)
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांकः

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3– मा0 आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4– श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/
प्रभारी अधिकारी (खनिज)
झाँसी।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0)440/2023 नवीन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य में मा0 न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु वांछित अनुदेश (Instruction) निम्नवत् हैः–

1. प्रश्नगत क्षेत्र जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम–धमनौड़ के गाटा संख्या–1419 ख के खण्ड संख्या–1 में स्थित 24.0 हे0 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष,2019 में शामिल किये जाने से पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी,झाँसी वन प्रभाग,झाँसी के कार्यायल पत्र संख्या–2679/15–1 दिनांकः 07.03.2019 के द्वारा नियमानुसार वन अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त प्रश्नगत क्षेत्र को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष,2019 के पृष्ठ संख्या–53 टेबल संख्या–13 (List of Proposed mining Area in District Jhansi with Location of the area and quantity) के क्रमांक संख्या–1 में अंकित कर शामिल किया गया। **(संलग्नक–1 वन अनापत्ति दिनांकः 07.03.2019 एवं संलग्नकः–2 डी0एस0आर0,2019)**

2. जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम–धमनौड़ के गाटा संख्या–1419 ख के खण्ड संख्या–1 में स्थित 24.0 हे0 क्षेत्र पर धसान नदी तल स्थित बालू/मोरम का उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के अध्याय–4 के अन्तर्गत नियम–23(2)(क) एवं शासनादेश–1875(1)/86–2017 दिनांकः 14.08.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत पट्टा ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष (दिनांकः 11.01.2023 से दिनांकः 10.01.2028 तक) की अवधि हेतु श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी–एच0आई0जी0–ए/135, आशियाना प्रथम, तहसील व जिला–मुरादाबाद के पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित किया गया है। **(संलग्नक–3 शासनादेश दिनांकः 14.08.2017)**

3. उपरोक्त खनन पट्टा निष्पादित किये जाने से पूर्व मान्यता प्राप्त अर्ह व्यक्ति से खनन योजना तैयार कराकर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म से दिनांक 26.02.2020 को अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण उत्तर प्रदेश लखनऊ (SEIAA) से दिनांक 18.11.2022 को पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तरदाता संख्या–11 ने वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम–1981 एवं जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम–1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 05.03.2023 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ से Consent To Operate (CTO) भी प्राप्त किया गया है। इस प्रकार उत्तरदाता संख्या–11 विषयगत क्षेत्र में सभी विधिक आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त करने के उपरान्त बालू/मोरम का खनन/परिवहन कर रहा है, जिसमें पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं Consent To Operate (CTO) की शर्तों का प्रभावी अनुश्रण सम्बन्धित तहसील–गरौठा के तहसील स्तरीय टास्क फोर्स एवं क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,झाँसी की कार्यवाही की जाती है। **(संलग्नक–4 खनन योजना दिनांकः 26.02.2020, संलग्नक–5 पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांकः 18.11.2022 एवं संलग्नक–6 CTO दिनांक 05.03.2023)**

4. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42(ज) में उल्लिखित है कि ''पट्टेदार नदी तल में तीन मीटर की गहराई अथवा जलस्तर जो भी कम हों, के परे कोई खनन संक्रियायें नहीं करेगा और कोई खनन, जिलाधिकारी द्वारा ऐसे परीक्षण किये गये सुरक्षा क्षेत्र में नहीं किया जायेगा''। उक्त प्राविधानों को प्रभावी अनुश्रवण तहसील स्तरीय टास्क फॉर्स टीम द्वारा किया जाता है तथा अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध उक्त नियमावली,2021 के नियम–60(4) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

5. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र से बालू/मोरम खनन कर अन्य स्थान पर एकत्रित कर ली जाती है, जहां पर स्थापित वे–ब्रिज जिसमें 90 अंशीय कैमरे सर्वलायंश सिस्टम से जुड़े रहते है, जिसकी निगरानी में उपखनिजों के परिवहन उत्तरदाता–11 द्वारा कराया जाता है जिसमें अनियमिततायें परलक्षित होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध UPMDSS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन नोटिस निर्गत करने की प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

6. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र वर्ष,2019 में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया गया तथा MoEF&CC Notification No. S.0.141(E) Dated 15-Jan-2016, S.0.3611 (E) dated 25-July-2018, Sustainable Sand Mining Management Guidelines2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 के अनुसार जनपद–झाँसी में विधिमान्य खनन क्षेत्र एवं नये चिन्हित खनन क्षेत्रों के सम्बन्ध जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु शासनादेश दिनांकः 17.05.2023 के बिन्दु संख्या–6 में प्रभारी अधिकारी (खनिज) की अध्यक्षता मे उल्लिखित समिति एवं निदेशालय के पत्र दिनांकः 12.02.2024 की (एस0ओ0पी0) में Sub Divisional Committee (SDC) के सदस्यो को समाहित करते हुए विधिमान्य उपखनिज के खनन के क्षत्रों एवं नवीन खनन क्षेत्रों को Standard Operating Procedure (SOP) के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) को तैयार किये जाने हेतु समिति का गठित कर कार्यवाही की जा रही है। **(संलग्नक–7 SDC समिति गठित आदेश दिनांकः 20.04.2024)**

अतः उपरोक्तानुसार उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका बलहीन एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, जिसके दृष्टिग्त योजित याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
झाँसी।

क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक)
झाँसी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
झाँसी वन प्रभाग,
झाँसी

जिलाधिकारी,
झाँसी।

~~~~ 01 800

(55)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

पत्रांक– 2679 /15–1, दिनांक, झांसी, 7-3-2019

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

विषयः– नई खनन नीति वर्ष 2017 के अनुसार उप खनिजों के दीर्घकालीन अवधि के खनन पट्टों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–769 / 30एम0एम0सी0 / 2018–19, दिनांक 04.07.2018।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद झांसी में उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रख्यापित नई खनन नीति 2017 के अनुसार उपखनिज बालू / मोरम को दीर्घकालीन अवधि हेतु ई–नीलामी सहित ई–निविदा के माध्यम से स्वीकृत किया जाना है, जिसके लिये जनपद झांसी के निम्नलिखित क्षेत्र को उक्त व्यवस्था के अनुसार दीर्घकालीन अवधि पर उठाये जाने हेतु वन विभाग की अनापत्ति चाही गयी है :–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	उपखनिज का नाम	तहसील	खनन क्षेत्र का नाम / ग्राम / नदी का नाम	गाटा सं0 / जोन सं0	रकवा (हे0 में)	रेंज का नाम
1	झांसी	बालू / मोरम	गरौठा	धमनौड़ / धसान	1419	24.00	बामौर

उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण संयुक्त रूप से खान अधिकारी, राजस्व विभागीय एवं वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा किया गया। संयुक्त निरीक्षणोंपरान्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, बामौर ने उक्त प्रस्तावित स्थल पर वन विभाग से सम्बन्धित आख्या निम्न प्रकार से प्रस्तुत की हैः–

1. प्रस्तावित क्षेत्र भारतीय वन अधिनियम 1927 (संशोधित अधिनियम 2001) की धारा 20 के अधीन आरक्षित वन भूमि अथवा उक्त अधिनियत की धारा–4 में वन भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि के बाहर है।
2. प्रस्तावित क्षेत्र धारा–4 अथवा धारा–20 में प्रस्तावित / आरक्षित वन भूमि की परिसीमा से 100 मी0 की दूरी से बाहर है।
3. प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि से वास्तविक दूरी 105 मीटर से अधिक है।
4. प्रस्तावित क्षेत्र की वन स्वरूप भूमि से दूरी 100 मी0 से अधिक है।
5. प्रस्तावित क्षेत्र विज्ञप्ति सं0–617 के अन्तर्गत नहीं है।
6. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि0मी0 के अन्तर्गत कोई सेन्चुरी क्षेत्र नहीं है।
7. उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में नदी तल में स्थित बालू मोरम के लिए खनन पट्टा दिया जा सकता हैं।
8. प्रस्तावित क्षेत्र में खनन से वन्य जीव व वन पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
9. प्रस्तावित क्षेत्र में वन उत्पाद के अभिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। अभिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जायेगा।

अतः क्षेत्रीय वन अधिकारी, बामौर की उपरोक्तानुसार आख्या एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, मऊरानीपुर की संस्तुति दिनांक 06.03.2019 के आधार उक्त प्रस्तावित स्थल पर वन विभाग की अनापत्ति निम्न शर्तो के अधीन निर्गत की जाती हैं :–

1. खनन पट्टे का संयुक्त सर्वेक्षण खनन अधिकारी की टीम, वन विभाग की टीम व राजस्व विभाग की टीम के साथ चिन्हिकरण एवं पिलरों के द्वारा सीमांकन के पश्चात ही खनन कार्य किया जायेगा।
~~~~

(54)

राजस्व विभाग के अभिलेखों में प्रस्तावित स्थल में किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो अनापत्ति पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

2. अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विवरण के अनुसार दिये गये क्षेत्रफल व गाटाओं के लिए है। इससे इतर किये गये खनन को अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा।

3. अभिवहन में वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. प्रस्तावित भूमि का धारा–4 होता हैं तो यह अनापत्ति स्वयं निरस्त समझी जायेगी।

5. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करते हुए स्थल पर मौजूद वृक्षों को यथावत् रहने दिया जायेगा तथा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

6. खनन स्थल के आस–पास स्थित वृक्षों, वन्य जीवों एवं जलीय जीवों को एवं उनके प्राकृतिक अधिवास को कोई हानि नहीं पहुंचायी जायेगी।

7. यदि खनन स्थल नदी क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है तब नदी का बहाव परिवर्तित होने के कारण परिवर्तित स्थल से खनन हेतु पुनः अनापत्ति प्राप्त करनी होगी ।

8. उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978 यथा संशोधित 2004 के अनुसार अभिवहन शुल्क संबंधित व्यक्ति/पट्टाधारक को नियमानुसार वन विभाग को देय होगा।

9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन हेतु पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को न स्वीकृत किया जाय जिसके विरूद्व पूर्व में वन अपराध दर्ज हो या जिसका अपराधिक इतिहास हो ।

10. खनन पट्टा प्राप्तकर्ता द्वारा जितने क्षेत्रफल में खनन किया जा रहा है। उतने क्षेत्रफल में अथवा न्यूनतम एक एकड़ क्षेत्रफल में स्थानीय प्रजाति के 200 फलदार/छायादार वृक्षों का रोपण सिंचाई एवं फैंसिग के साथ अपने निजी स्त्रोतो से करेगें। एक एकड़ या इससे अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टों की अनापत्ति के मामलें में प्रति एकड़ 200 वृक्ष उपरोक्तानुसार लगाना होगा।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मऊरानीपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बामौर।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

802

District Survey Report

For

(Planning & Execution of) Minor Mineral Excavation

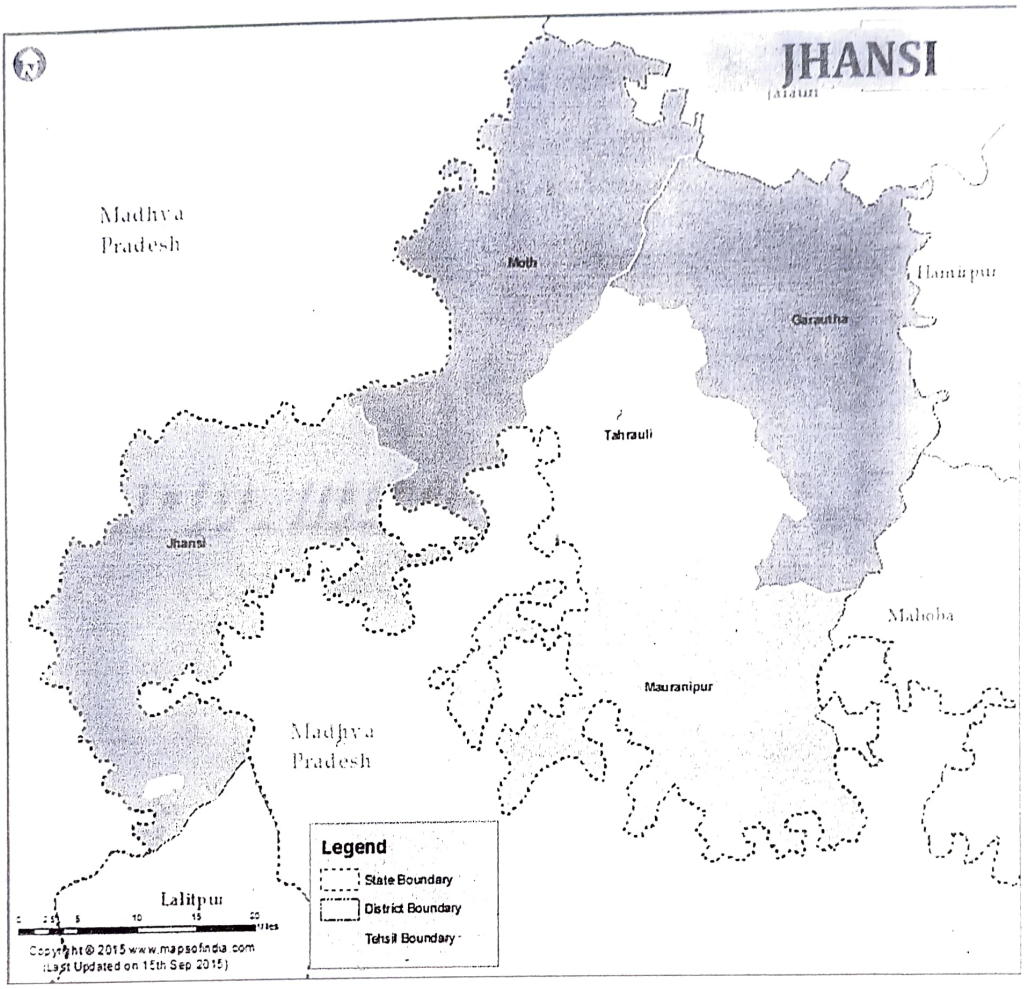

Chairman,
District Environmental Impact Assessment Authority,
Jhansi, U.P.

&

District Mining Officer – Jhansi

(शे० महबूब)
जिला खान अधिकारी
झाँसी

(शिव सहाय अवस्थी)
जिलाधिकारी, झाँसी

Content

1. Preface
2. Introduction
3. General Profile of the district
   - Climate Condition
   - Rainfall and humidity
   - Topography & Terrain
   - Water Course & Hydrology
   - Ground Water Development
   - Drainage System
   - Socio-economics
   - Cropping Pattern
   - Land Form and Seismidistrict
   - Flora
   - Fauna
4. Physiography of the district
5. Land use pattern of the district
6. Geology
   - Geology
   - Lithology
7. Mineral wealth
   - Soil
   - Sand
   - Description of River
8. Process of deposition
   - Mode of sediment transport
   - Sediment transport in rivers
   - Sediment Influx Rate
   - Recharge Rate
   - Estimation of Sedimentation
   - Sedimentation Yield
9. Overview of mining activity in the district
   - Reserve Estimation
   - Detail of Production Of Sand / Bajri or Minor Mineral in Last Three Years in Distt.

Overview of mining activity in the district

Table 7: Detail of Production of Sand / Bajri or Minor Mineral in Last Three Years in District Jhansi

Sr No.	Year	Production of Minor Mineral (in Cum)
1.	2014-2015	2573434.36
2.	2015-2016	4472639.29
3.	2016-2017	2434843.03

Table 8: Details of Royalty or Revenue Received In Last Three Years

Sr No.	Year	Revenue Received
1.	2014-2015	Rs.50,28,14,980
2.	2015-2016	Rs.54,69,15,187
3.	2016-2017	Rs. 62,10,54,766

Table 9: List of Mining Quarries in the District with Location, Area and Period of Validity

Sl. No	Tehsil	Village	Gata No. / Khand No.	Area (Ha)	Name of Minor Mineral	Estimated Volume of Mineral (in Cum)	River
1	Garautha	Devri	380/10, 332/1	21.044	Sand/Morram		Ghasan
2	Garautha	Behiter	522gha	14.164	Sand/Morram		Betwa
3	Garautha	Kharwach	434	24.281	Sand/Morram		Ghasan
4	Garautha	Dekaule	1129	12.140	Sand/Morram		Betwa

5	Garautha	Tharro	01, 319	20.234	Sand/Morram		Betwa
6	Garautha	Tehraka	278, 293	20.234	Sand/Morram		Betwa
7	Garautha	Erach	01	40.468	Sand/Morram		Betwa
8	Tahraule	Shamsherpura	01	12.140	Sand/Morram		Betwa
9	Tahraule	Kukar Gav	01ka	30.361	Sand/Morram		Betwa
10	Tahraule	Luhar Gav	01	12.140	Sand/Morram		Betwa
11	Moth	Paraicha	184	8.903	Sand/Morram		Betwa
12	Moth	Chelra	1055, 1107	16.187	Sand/Morram		Betwa
13	Mauraniprur	Melwara	950, 966	14.164	Sand/Morram		Mauranepur
14	Mauranipru	Pachauro	968, 796, 797, 1102	8.093	Sand/Morram		Mauranepur
15	Mauranipru	Dhawakar	1984, 2009	12.140	Sand/Morram		Mauranepur

Table 10: List of Mining permits in the District with Location, Area and Period of Validity

Sl. No	Tehsil	Village	Gata No. / Khand No.	Area (Ha)	Name of Minor Mineral	Estimated Volume of Mineral (in Cum)
1	Jhansi	Senkar	263	8.00	Sand/Morram	16184
2	Jhansi	Baghaura	563	10.00	Sand/Morram	30345
3	Jhansi	Gangawale	1	10.00	Sand/Morram	10115
4	Jhansi	Khereyapale	1	9.00	Sand/Morram	9103
5	Jhansi	Bargarh	143	8.50	Sand/Morram	8557
6	Garautha	Dhekaure	1129	10.00	Sand/Morram	40460
7	Garautha	Kudri	1, 218mi	10.00	Sand/Morram	80920
8	Garautha	Arich	502	10.00	Sand/Morram	40460
9	Garautha	Tharro	1	8.50	Sand/Morram	17195
10	Mauraniprur	Khakaura	523	10.00	Sand/Morram	40460
11	Mauraniprur	Dhawakar	1984mi	6.00	Sand/Morram	12138
12	Mauraniprur	Pachauro	968, 1019	10.00	Sand/Morram	20230
13	Tahraule	Luhar gav ghat	1	10.00	Sand/Morram	80920
14	Tahraule	Shamsherpura	01	10.00	Sand/Morram	60690
15	Moth	Velera	1107	10.00	Sand/Morram	40460
16	Moth	Paraicha	184/4	10.00	Sand/Morram	40460

Table 11:- Details of Production of Sand/ Bajari or Minor Minerals in last 3 Years in District Jhansi

Sr No.	Year	Production of Minor Minerals (in Cum.)
1.	2016-2017	2,43,4843.03
2.	2017-2018	1,79,850.00
3.	2018-2019	2,25,6000.00

Table 12:- Details of Royalty or Revenue Received in the Last 3 Years.

Sr No.	Financial Year	Revenue Received
1.	2016-2017	62,10,54,766.00
2.	2017-2018	20,2,45,57,326.00
3.	2018-2019	1,27,84,24,854.00

Table 13:- List of Proposed Mining areas in District Jhansi With Location Area and Quantity

Sl. No.	Tehsil	Village	Gata No. / Khand No.	Area (Ha)	Name of Minor Mineral	Estimated Volume of Mineral (in Cum)	River
1	Garautha	Dhamnad	1419 (Khand -1)	24.00	Sand/ Morrum	250,000.00	Dhasan
2	Garautha	Dhamnad	448, 449, 1193 (Khand-2)	20.00	Sand/ Morrum	70,000.00	Dhasan
3	Garautha	Kharwanch	908 (Khand -2)	20.00	Sand/ Morrum	180,000.00	Dhasan
4	Garautha	Devari	332/1 (Khand -2)	10.00	Sand/ Morrum	60,000.00	Dhasan
5	Garautha	Teharka	01, 277	13.00	Sand/	52,000.00	Betwa

			(Khand -2)		Morrum		
6	Garautha	Khama	01, 470	12.00	Sand/ Morrum	48,000.00	Betwa
7	Garautha	Kudri	01, 218	14.00	Sand/ Morrum	80,000.00	Betwa
8*	Garautha	Motikatra	1419 (Khand -1)	24.00	Sand/ Morrum	250,000.00	Dhasan
9*	Garautha	Motikatra	1419 (Khand -2)	24.00	Sand/ Morrum	220,000.00	Dhasan
10.	Moth	Salemapur	321	10.00	Sand/ Morrum	50,000.00	Betwa
11	Mauranipur	Nawada	373, 374, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 782, 800, 692	5.00	Sand/ Morrum	15,000.00	Managoru
12	Mauranipur	Atpei	794	2.50	Sand/ Morrum	8,000.00	Managoru
13	Mauranipur	Atpei / Nawada	28, 67, 73, 76 & Nawada 872	14.00	Sand/ Morrum	70,000.00	Saprar
14	Mauranipur	Khakaura	523	20.00	Sand/ Morrum	150,000.00	Dhasan
15	Mauranipur	Dhawakar/ Sitora	1984& Sitora 1	9.00	Sand/ Morrum	35,000.00	Sukhnai

Note - NOC FROM FOREST DEPARTEMNT IS UNDER PROCESS.*

Table 14:- List of Operative Mines of Sand / Morrum in District Jhansi

Sr. No.	Name & Address	Details of Lease Area				Period
		Tehsil	Village	Gata No.	Area (Ha.)	
1.	R.S.I. World Pvt. Ltd.: M/s Shri Kailash Chandra Gupta S/o Shri Murari Lal Gupta, Residence – E – 7/M 708, Arera Colony, Bhopal	Garautha	Devari	308/10,332/1	21.044	19.02.2018 to 18.02.2023

	(M.P.)					
2.	Vikram Construction Company.: R/o- Near Bharat Mandir, Chirgaon Road, Jhansi	Garautha	Kharwanch	434	24.281	19.03.2018 to 18.03.2023
3.	Ambey Suppliers Pvt. Ltd. R/o- W 21, Ist Story Rajauri Garden , New Delhi	Garautha	Erach	01	40.468	10.12.2018 to 09.12.2023
4.	Ashish Yadav R/o- Village & Post Banagaon, Tehsil & Distt. Jhansi	Tahrauli	Shamsherpura	01	12.140	04.04.2018 to 03.04.2023
5.	Mayank Tomar R/o- 126, Bapu Nagar, Bhilwara (Rajasthan)	Mauranipur	Dhawakar	1984, 2009	12.140	07.04.2018 to 06.04.2023

Ordinary earth and Sand has become very important minerals for our society due to its many uses. Ordinary earth can be used for making brick, filling roads, whereas sand may be used as building sites, brick-making, making glass, sandpapers, reclamations, and etc. The role of sand is very vital with regards to the protection of the coastal environment. It acts as a buffer against strong tidal waves

20.	REPORT OF THE COMMITTEE CONSTITUTED FOR PREPARATION OF GUIDELINES FOR WORKS ON DE-SILTATION FROM BHIMGAUDA (UTTARAKHAND) TO FARAKKA (WEST BENGAL), by Government of India Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation National Mission for Clean Ganga (2017).
21.	River Sand Mining Management Guideline, Ministry Of Natural Resources And Environment Department Of Irrigation And Drainage, Malaysia
22.	Statistical Bulletin, 2006, District Jhansi
23.	"Sediment yield runoff-drainage area relationships in the United States" (1976). Dendy , F.E. and Bolton, G.C. , Journal of Soil And Water Conservation, Nov-Dec, 1976, Pg-264-266.
24.	Singh, I.B., Ansari, A.A., Chandel, R.S. and Misra, A., 1996. Neotectonic control on drainage system in Gangetic Plain, Uttar Pradesh. Journal of the Geological Society of India, 47, 599–609.
25.	Survey of India Toposheet
26.	Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016,MoEF & CC, Government of India, New Delhi
27.	Tangri A.K., Ram Chandra & S.K.S.Yadav (2000) –.Detrital influxes in the melt- water of Gangotri Glacier, Garhwal Himalaya. Nat.Sem. on Geodynamics & Environmental Management of Himalaya, Srinagar (Garhwal), Dec.4th-6th, 2000.
28.	The Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 1963
29.	The Environmental (Protection)Act, 1986 and Amendments
30.	Uttar Pradesh, District Gazetteers, Jhansi, 1988

(मो० महबूब)
जिला खान अधिकारी
झाँसी

(शिव सहाय अवस्थी)
जिलाधिकारी, झाँसी

संख्या-24/2017/1875/86-2017-57(सामान्य)/2017टीसी-1

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 14 अगस्त 2017**

विषयः प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-1498 वर्ष 2015 गुलाब चन्द्र मिश्र बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.05.2017 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम 9क को विलोपित करते हुए नियमावली के 43वें संशोधन द्वारा अध्याय-4 में संशोधन कर ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से क्षेत्रों के परिहार पर दिए जाने का प्राविधान किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 यथा संशोधित के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी (E-Tender cum E-Auction) प्रणाली के माध्यम से परिहार पर दिये जाने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेंगी:-

1. नदी तल स्थित उपखनिजों के रिक्त क्षेत्रों को खनिज की उपलब्धता, परिवहन मार्ग की स्थिति, क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलता तथा सुरक्षित खनन के दृष्टिगत अधिकतम 03 मी0 की गहराई अथवा जल स्तर, जो भी पहले हो, तक खनिज की मात्रा का आकलन करते हुए व्यवसायिक रूप से उपयुक्त खण्डों का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित खण्डों का क्षेत्रफल 05 हे0 से कम नही होगा। वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त न होने की स्थिति में छोटे रिक्त खण्डों का निर्धारण किया जा सकता है परन्तु ऐसे निर्धारण के पूर्व युक्तियुक्त कारण अभिलिखित किया जायेगा। निर्धारित खण्डों के लिए वन विभाग की अनापत्ति अनिवार्य है।
2. ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल स्थित उपखनिजों के खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेगें। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
3. ई निविदा सह ई नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नही होगी। इससे भिन्न बिड/ बोली दिये जाने पर बिड/ बोली स्वीकार नही की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/ बोली की दर (रूपया प्रति घन मी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (E-Tender) देने का मौका प्रदत होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नही किया जा सकेगा। ई निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढा सकते है।
5. किसी क्षेत्र के ई निविदा सह ई नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
6. निर्धारित खण्डों में उपखनिज की खनन योग्य मात्रा एवं उस क्षेत्र के अर्नेस्ट मनी का निर्धारण उपरोक्त प्रस्तरों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति जिसमें अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार तथा जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक होंगे, द्वारा कराया जायेगा।
7. एम0एस0 टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।
8. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing type डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम एस टी सी के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेगें।
9. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू0-15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
10. ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनर्लाइन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी द्वारा भेजा गया सूचना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित रू0-1,180 (रू0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।
11. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा **स्वप्रमाणित** निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा:-
    (1) आवेदक का आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामलें में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वैब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नही किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहॉ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हों।

(3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।

(4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई निविदा सह ई नीलामी से सम्बन्धित समस्त वितीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति,

(5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहॉ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नही करता है वहा ॅ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।

12.एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म /कम्पनी ई निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नही ले सकते है:-

(1) जो भारतीय राष्ट्रिक नही है

(2) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।

(3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नही कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

(4) जिसने अपना आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

(5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(6) फर्म/कम्पनी के मामलें में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

13.रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन - खण्डों का निर्धारण एवं उसका मूल्यांकन होने के उपरान्त नियमावली-1963 के नियम-23 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा निम्न प्रक्रिया के अनुसार रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com, दैनिक समाचार पत्रों एवं विज्ञापन पट (नोटिस बोर्ड) पर प्रकाशित किया जायेगा।

(1) जिलाधिकारी द्वारा नियम 23(1) की घोषणा होने के उपरान्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-निलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए ई-निविदा के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस (सूचना)/विज्ञप्ति प्रकाशित किया जायेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सम्पूर्ण विवरण एम0एस0टी0सी0 को भी ईमेल से उपलब्ध कराया जायेगा ताकि क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों का विवरण एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर डालने के बाद इसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के दो सदस्यों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा। डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि के उपरान्त ही क्षेत्रों का विवरण ई निविदा सह ई नीलामी हेतु एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल पर बिडर्स एवं सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होगा।

(2) विज्ञप्ति में क्षेत्रों का विवरण यथा ग्राम, गाटा सं0/खण्ड सं0, नदी का नाम क्षेत्रफल, क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा, उपखनिज की रायल्टी दर, क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री बिड अर्नेस्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मनी, ई-निविदा डालने की तिथि व अवधि, ई-निविदा के उपरान्त ई-नीलामी का समय व दिनांक, ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया, शर्तो का विवरण आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(3) ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल **www.mstcecommerce.com** पर देखा जा सकता है।

(4) रिक्त क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रर्दशित की जायेगी इसके साथ ही स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये, जिससे कि किसी भी दशा में उक्त पोर्टल एवं समाचार पत्रों मे प्रकाशित विज्ञप्ति में कोई भी भिन्नता न हो। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना (नोटिस) निम्नानुसार प्रकाशित की जायेगी:-

क. नोटिस की प्रतियां जिलाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर चिपकायी जायेंगी।

ख. नोटिस की एक प्रति एम0एस0टी0सी0 द्वारा निर्धारित पोर्टल, विभागीय वेबसाईट, राज्य सरकार के ई-टेण्डर/ई-ऑक्शन पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

ग. सर्वसाधारण की सूचना के लिए नोटिस जिलें में प्रचलित कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

(5) समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से ही विज्ञप्ति की तिथि की गणना की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से कम से कम 30 दिन पश्चात् ही ई-निविदा प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की जायेगी। 30 दिन के पश्चात् आगामी 04 दिन तक ई-निविदा प्राप्त की जायेगी।

(6) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक रू0-15000 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

(7) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानें की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।

(8) जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।

(9) अधिकतम पॉच खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नही किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पाॅच क्षेत्र अथवा 400 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होगें। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे0 से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इटेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

14. जिलाधिकारी द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया को सम्पादित करते हेतु निम्नानुसार निविदा समिति का गठन किया जायेगा:-

(1) जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनन, (अध्यक्ष)

(2) जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी, (सदस्य)

(3) जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, (सदस्य सचिव)

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिलाधिकारी तथा समिति के सभी सदस्यों का डिजिटल सिग्नेचर (Class III Signing Cum Encryption) का होना आवश्यक है, यदि किसी सदस्य का उक्त डिजीटल सिग्नेचर नही है तो उसे तत्काल बनवा लिया जाय।

15. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया:-

(1) ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तगत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नही होगा। द्वितीय चरण में ई निविदा में प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई नीलामी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्प्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार आनलाईन बोली में भाग लेंगे।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड(आफर) में प्रतिघन मीटर में दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पॉच या पॉच से कम बिड प्राप्त होता है, तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पॉच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते है तब केवल पॉच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तर-15(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के याग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते है।

(4) द्वितीय चरण में ई नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

(5) द्वितीय चरण की नीलामी की प्रक्रिया में नीलामी की निर्धारित अवधि के भीतर इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की ऑनलाइन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।

(6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नही दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय मंे यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नही होती है।

(7) ई निविदा सह ई नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	प्रथम दिन
प्रथम चरण ई निविदा (ई टेण्डर) की अवधि	31वें दिन (पूर्वाह्न 10.00 बजे) से 34वें दिन (सांय 05.00 बजे) तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा(बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	35वें दिन से 36वें दिन तक
द्वितीय चरण ई नीलामी की अवधि	37वें अथवा उसके बाद के दिन जैसा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक) अथवा (अपराह्न 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक)

(8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन:

क. प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नही को भी लॉगिन कर जान सकते है।

ख. एकल निविदा के मामलो को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

16. **पट्टे का दिया जाना:** नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई नीलामी के मामलें में उस बोली या प्रस्ताव को प्रस्तर-15(2) मे दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता /निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

17. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख की सत्यापन की स्थिति में अभिलेख सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को पेषित की जायेगी। अभिलेख सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नही किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

18. **लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे:-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया घन प्रति मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तो का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षो में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन कराया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम-34 के प्राविधानों के अन्तगत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वितीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

19. **सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति:**

(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि एम0एस0टी0सी0 के ई पेमेन्ट गेट वे पर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता /निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा।

(3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0), आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

20. **शर्तें:- विज्ञप्ति में निम्न शर्तें दी जायेंगी:-**

(1) ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

(2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शायें गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।

(3) पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाति करेगा।

(4) पट्टा धारक नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

(5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-1963 के नियम-59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नही करेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नही किया जायेगा।

(8) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहॉ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहॉ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बतानें की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

(12) नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

(13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

(14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये।

अतः उपरोक्तानुसार ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से क्षेत्रों का व्यवस्थित करने की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र सम्पादित कर ली जाये।

संलग्नक-(1) नियमावली, 1963 की चतुर्थ अनुसूची।

(2) विज्ञप्ति का प्रारूप।

भवदीय,

राज प्रताप सिंह

अपर मुख्य सचिव

संख्या- 1875(1)/86-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महाप्रबंधक (बी0ओ0) एम0एस0टी0सी0 लि0 लीलावती बिल्डिंग द्वितीय तल, 69 अरमेनियम स्ट्रीट, चेन्नई।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)

संयुक्त सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

819 04.

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन, लखनऊ।

(114)

सेवा में

जिलाधिकारी
झांसी।

संख्याः–1927 /मा0 प्लान/2017 दिनांक 26/02/2020

विषयः– पट्टाधारक श्री विपिन कुमार सक्सैना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सैना के पक्ष में स्वीकृत जनपद–झांसी की तहसील–गरौठा, ग्राम–धमनौड़, गाटा सं0–1419(खण्ड–1), क्षेत्रफल 24.0 हे0, में उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन योजना का अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि उक्त संदर्भित क्षेत्र के संबंध में पट्टाधारक श्री विपिन कुमार सक्सैना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सैना द्वारा प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन उत्तर प्रदेश उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–34 के उपनियम (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.02.2020 को कर दिया गया है।

1– "खनन योजना" का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया गया हैः–

(अ) "खनन योजना" का अनुमोदन खनन पट्टा विलेख निष्पादन के दिनांक से आगमी 05 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। खनन क्षेत्र से 250000 घन मी0 प्रति वर्ष खनिज का उत्पादन अनुमन्य किया गया है।

(ब) अनुमोदित अवधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते है, तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व पट्टेदार का होगा।

(स) आबद्ध नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का दायित्व पट्टेदार का होगा।

(द) अनुमोदित खनन योजना की एक–एक प्रमाणित प्रति संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व भी पट्टेदार का होगा।

(च) अनुमोदित खनन योजना में विनिहित प्रकिया के अनुसार पट्टेदार द्वारा खनन कार्य न किये जाने के पाये जाने पर पट्टेदार के विरूद्ध पट्टे की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

(छ) खनन योजना को निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ अनुमोदित किया जाता हैः–

1. बेंच की ऊँचाई अधिकतम 01 मी0 एवं बेंच की चौडाई न्यूनतम 10 मी0 होनी चाहिए।
2. खनन कार्य अधिकतम 03 मी0 की गहराई तक या पानी निकलने के तल, जो भी कम हो तक किया जायेगा।
3. खनन कार्य जीरो (0) लेवल से ऊपर की ओर किया जायेगा।
4. खनन पट्टा स्थल पर फर्स्ट एड बॉक्स व स्ट्रेचर रखे जायें।

MP-letter

113

5. श्रमिकों के लिये श्रमिक विश्राम गृह उनके पीने के पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जायें।
6. खनन क्षेत्र से मुख्य मार्ग तक जाने वाले पहुँच मार्ग (कच्चे मार्ग) पर नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जायेगा, ताकि वाहनों के आवागमन से उत्पन्न धूल को उड़ने से रोका जा सके।
7. नदी के तटबन्ध से नदी की ओर न्यूनतम 50 मी0 तक खनन कार्य किया जाना वर्जित होगा। जहॉ तक व्यवहारिक हो नदी से तटबन्ध की ओर खनन किया जायेगा।
8. खनन कार्य से निकाले गये मलवे खास कर टॉप स्वायल को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जायेगा।
9. पर्यावरण स्वच्छता के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

2– अस्तु आपसे अनुरोध है कि अनुमोदित खनन योजना की संलग्न मूल प्रति सम्बन्धित पट्टेदार को अनुपालन हेतु उपलब्ध करा कर उनसे प्राप्ति रसीद प्राप्त कर निदेशालय को भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्नकः यथोपरि ।

भवदीय,

(अनिल कुमार शर्मा)
मुख्य खान अधिकारी
कृते निदेशक।

संख्याः (1)/मा0 प्लान/2017 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, जनपद– झांसी।
2–पट्टाधारक श्री विपिन कुमार सक्सैना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सैना नि0 एम0आई0जी0–ए/135, आशियाना प्रथम तहसील व जिला मुरादाबाद।
3–खनन अनुभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

(अनिल कुमार शर्मा)
मुख्य खान अधिकारी
कृते निदेशक।

821

ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), Uttar Pradesh)

To,

The Owner
VIPIN KUMAR SAXENA
R/o-MIG-A/135 Aashiyana Prtham Teh Distt Moradabad UP -244001

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/UP/MIN/56882/2020 dated 22 Sep 2020. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC22B001UP110182**
2.	**File No.**	5860/5578
3.	**Project Type**	New
4.	**Category**	B1
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	1(a) Mining of minerals
6.	**Name of Project**	Area 24.00 Ha On Dhasan River for Sand/Morrum Mining Project at Gata No.-1419 Kha Khand No.01 Village-Dhamnaud, Tehsil-Garautha, District-Jhansi, U.P.
7.	**Name of Company/Organization**	VIPIN KUMAR SAXENA
8.	**Location of Project**	Uttar Pradesh
9.	**TOR Date**	08 Jun 2020

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 18/11/2022

(e-signed)
Member Secretary
Member Secretary
SEIAA - (Uttar Pradesh)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow- 226010
E-Mail- doeuplko@yahoo.com, seiaaup@yahoo.com
Phone no- 0522-2300541

Reference- MoEFCC Proposal no- SIA/UP/MIN/56882/2020 & SEIAA, U.P File no-5860-5578

Sub: Environmental Clearance for Proposed Sand/Morrum Mining from Dhasan Riverbed at Gata No. 1419 Kh Khand No.- 01, Village- Dhamnaud, Tehsil- Garautha ,District- Jhansi U.P., (Leased Area – 24.00 Ha).

Dear Sir,

This is with reference to your application / letter dated 04-03-2020, 20-05-2020, 22-09-2020, 28-09-2020, 09-10-2020, 05-10-2020, 13-10-2020, 11-08-2021 on above mentioned subject. The matter was considered by 678th SEAC in meeting held on 08-08-2022, 693th SEAC in meeting held on 12-10-2022 and 668th SEIAA in meeting held on 10-11-2022.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s Paramarsh (Servicing Environment and Development), Lucknow, UP to SEAC on 08-08-2022 & 12-10-2022.

Project Details Informed by the Project Proponent and their Consultant

The project proponent, through the documents and presentation gave following details about their project –

1. The environmental clearance is sought for Sand/Morrum Mining from Dhasan Riverbed at Gata No. 1419 Kh Khand No.- 01Village- Dhamnaud, Tehsil- Garautha ,District- Jhansi U.P., (Leased Area – 24.00 Ha).
2. The terms of reference in the matter were issued by SEIAA, U.P. vide letter no. 110/Parya/SEAC/5578/2019 dated 08/06/2020.
3. The fresh public hearing was organized on 06/05/2022 in the Meeting Hall Tehsil- Garautha District – Jhansi. U.P.
4. Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1.	On Line Proposal No.	SIA/UP/MIN/56882/2020
2.	File No. allotted by SEIAA, UP	5860/5578
3.	Name of Proponent	Sri Vipin Kumar Saxena S/o Sri Om Prakash Saxena
4.	Full correspondence address of proponent and mobile no.	R/o- MIG –A/135 , Aashiyana Pratham , Tehsil and District Moradabad U.P
5.	Name of Project	Sand Morrum Mining
6.	Project Location(Plot.Khsra/Gata No.)	Khand No.- 01Gata No. 1419 Kh
7.	Name of River	Dhasan River
8.	Name of Village	Dhamnaud
9.	Tehsil	Garautha
10.	District	Jhansi
11.	Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12.	Sanctioned Lease Area (in Ha.)	24.0 Ha.
13.	Max. & Min mRL within lease area	121.0 mRL & 128.5 mRL
14.	Pillar Coordinates (Verified by DMO)	POINT / LATTITUDE / LONGITUDE A / 25°40'42.00"N / 79°23'00.70"E B / 25°40'51.10"N / 79°23'04.40"E

		C	25°40'59.60"N	79°23'06.10"E
		D	25°41'04.40"N	79°23'04.10"E
		E	25°41'08.80"N	79°23'01.50"E
		F	25°41'11.80"N	79°22'58.40"E
		G	25°41'15.60"N	79°22'52.10"E
		H	25°41'22.17"N	79°22'37.78"E
		I	25°41'25.13"N	79°22'38.44"E
		J	25°41'20.80"N	79°22'54.50"E
		K	25°41'16.30"N	79°23'03.60"E
		L	25°41'07.90"N	79°23'10.00"E
		M	25°40'57.30"N	79°23'11.60"E
		N	25°40'54.80"N	79°23'10.90"E
		O	25°40'48.30"N	79°23'08.40"E
		P	25°40'40.31"N	79°23'03.62"E

15.	Total Geological Reserves	7,20,000m^3 /Annum	
16.	Total Mineable Reserve	2,55,767m^3 /Annum	
17.	Proposed Production/ Year	2,50,000 m^3	
18.	Sanctioned Period of Mine lease	5 Years	
19.	Method of Mining	Open cast Manual / Semi Mechanized Mining Method/Bar Scalping or skim mining (as per IBM rules & SSMMG, 2016)	
20.	No. of working days	225 Days	
21.	Working hours/day	8 Hours	
22.	No. of workers	90 Worker	
23.	No. of vehicles movement/day	123Trucks / Day	
24.	Type of Land	River Bed (Govt. Land)	
25.	Ultimate of Depth of Mining	1.3 m	
26.	Nearest metalled road from site	1.0 Km	
27.	Water Requirement	PURPOSE	REQUIREMENT (KLD)
		Drinking	0.9
		Suppression of dust	12.0
		Plantation	3.17
		Others (if any)	-
		Total	16.07 KLD
28.	Name of QCI Accredited Consultant with QCI No and period of validity.	Ind Tech House Consult Certificate No-NABET/EIA/1821/RA0098 Period of Validity- 24-10-2022	
29.	Any litigation pending against the project or land in any court	No	
30.	Details of 500 m Cluster Map & Certificate verified by Mining Officer	Letter No1630/30 M.M.C /(2019-20) Date-03.02.2020	
31.	Details of Lease Area in approved DSR	Yes (Page No: 52, Table No:13 & Sr, No: 01)	
32.	Proposed EMP cost	23.01 Lac	
33	Proposed total Project cost	1.08 Crore	
34.	Length and breadth of Haul Road	1000 mtr Length & 6m width haulage road	
35.	No. of Trees to be Planted	792 Trees	
36.	Monitoring Period	October 2020 – December 2020	

5. The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.

6. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.
7. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
8. There is no litigation pending in any court regarding this project.
9. The project proposal falls under category–1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee Meeting (SEAC) held on 08-08-2022 & 12-10-2022 the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) in its Meeting held 10-11-2022 and decided to grant the Environmental Clearance to the title project for collection of 2,50,000 m^3 /Annum lease area of 24 ha subject to effective implementation of the following General Conditions and specific conditions:-

General condition:

1. This environmental clearance is subject to allotment of mining lease in favour of project proponent by District Administration/Mining Department.
2. Forest clearance shall be taken by the proponent as necessary under law.
3. Any change in mining area, khasra numbers, entailing capacity addition with change in process and or mining technology, modernization and scope of working shall again require prior Environmental Clearance as per the provisions of EIA Notification, 2006 (as amended).
4. Precise mining area will be jointly demarcated at site by project proponent and officials of Mining/Revenue department prior to starting of mining operations. Such site plan, duly verified by competent authority along-with copy of the Environmental Clearance letter will be displayed on a hoarding/board at the site. A copy of site plan will also be submitted to SEIAA within a period of 02 months.
5. Mining and loading shall be done only within day hours' time.
6. No mining shall be carried out in the safety zone of any bridge and/or embankment.
7. It shall be ensured that standards related to ambient air quality/effluent as prescribed by the Ministry of Environment & Forests are strictly complied with. Water sprinklers and other dust control majors should be applied to take-care of dust generated during mining operation. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.
8. All necessary statutory clearances shall be obtained before start of mining operations. If this condition is violated, the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.
9. Parking of vehicles should not be made on public places.
10. No tree-felling will be done in the leased area, except only with the permission of Forest Department.
11. No wildlife habitat will be infringed.
12. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out.
13. It shall be ensured that mining operation of Sand/Moram will not in any way disturb the, velocity and flow pattern of the river water significantly.
14. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting. A report on the same, vetted by the competent authority shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within 02 months.
15. Primary survey of flora and fauna shall be carried out and data shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months.
16. Hydro-geological study shall be carried out by a reputed organization/institute within six months and establish that mining in the said area will not adversely affect the ground water regime. The report shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months. In case adverse impact is observed /anticipated, mining shall not be carried out.

17. Adequate protection against dust and other environmental pollution due to mining shall be made so that the habitations (if any) close by the lease area are not adversely affected. The status of implementation of measures taken shall be reported to the RO, UPPCB and SEIAA and this activity should be completed before the start of sand mining.
18. Need-based assessment for the nearby villages shall be conducted to study economic measures which can help in improving the quality of life of economically weaker section of society. Income generating projects/tools such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. can form a part of such program me. The project proponent shall provide separate budget for community development activities and income generating programmes.
19. Green cover development shall be carried out following CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/Horticulture Officer.
20. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil, if any, and the top soil should be utilized for green cover/tree plantation.
21. Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.
22. An Environmental Audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the SEIAA.
23. The District Mining Officer should quarterly monitor compliance of the stipulated conditions. The project proponent will extend full cooperation to the District Mining Officer by furnishing the requisite data/information/monitoring reports. In case of any violations of stipulated conditions the District Mining Officer will report to SEIAA.
24. The project proponent shall submit six monthly reports on the status of compliance of the stipulated environmental clearance conditions including results of monitored data (both in hard & soft copies) to the SEIAA, the District Officer and the respective Regional Office of the State Pollution Control Board by 1st June and 1st December every year.
25. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parisad/ Municipal Corporation and Urban Local Body.
26. Transportation of materials shall be done by covering the trucks / tractors with tarpaulin or other suitable mechanism to avoid fugitive emissions and spillage of mineral/dust.
27. Waste water, from temporary habitation campus be properly collected & treated before discharging into water bodies the treated effluent should conform to the standards prescribed by MoEF/CPCB.
28. Measures shall be taken for control of noise level to the limits prescribed by C.P.C.B.
29. Special Measures shall be adopted to protect the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of Village roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out by the project proponent regularly at his own expenses.
30. Measure for prevention & control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion, if any, shall be carried-out with geo textile matting or other suitable material.
31. Under corporate social responsibility a sum of 5% of the total project cost or total income whichever is higher is to be earmarked for total lease period. Its budget is to be separately maintained. CER component shall be prepared based on need of local habitant. Income generating measures which can help in upliftment of poor section of society, consistent with the traditional skills of the people shall be identified. The programme can include activities such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, free distribution of smokeless Chula etc.
32. Possibility for adopting nearest three villages shall be explored and details of civic amenities such as roads, drinking water etc proposed to be provided at the project proponent's expenses shall be submitted within 02 months from the date of issuance of Environment Clearance.
33. The funds earmarked for environmental protection measures should be kept in separate account and should not be diverted for other purpose. Year wise expenditure should be reported to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, GoI, Lucknow, SEIAA, U.P and UPPCB.

34. Action plan with respect to suggestion/improvement and recommendations made and agreed during Public Hearing shall be submitted to the District mines Officer, concern Regional Officer of UPPCB and SEIAA within 02 months.
35. Environmental clearance is subject to obtaining clearance under the Wildlife (Protection) Act, 1972 from the competent authority, if applicable to this project.
36. The proponent shall observe every 15 day for nesting of any turtle in the area. Based on the observations so made, if turtle nesting is observed, necessary safeguard measures shall be taken in consultation with the State Wildlife Department. For the purpose, awareness shall be created amongst the workers about the nesting sites so that such sites, if any, are identified by the workers during operations of the mine for taking required safeguard measures. In this regards the safety notified zone should be left so that the habitat/nesting area is undisturbed.
37. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bed material and ensure that due to this activity the hydro geological regime of the surrounding area shall not be affected.
38. The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent Authorities for withdrawal of requisite quantity of water (surface water and groundwater), required for the project.
39. Appropriate mitigative measures shall be taken to prevent pollution of the river in consultation with the State Pollution Control Board. It shall be ensured that there is no leakage of oil and grease in the river from the vehicles used for transportation.
40. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles carrying the mineral shall not be overloaded.
41. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. (MoEF circular Dated : 22-09-2008 regarding stipulation of condition to improve the living conditions of construction labour at site).
42. Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Occupational health surveillance program of the workers should be undertaken periodically to observe any contractions due to exposure to dust and take corrective measures, if needed.
43. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parishad/ Municipal Corporation, Urban Local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions/ representations, if any, were received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.
44. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of environmental clearance conditions and shall also be sent to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, GoI, Lucknow by e-mail.
45. The green cover development/tree plantation is to be done in an area equivalent to 20% of the total leased area either on river bank or along road side (Avenue Plantation).
46. Debris from the river bed will be collected and stored at secured place and may be utilized for strengthen the embankment.
47. Safety measures to be taken for the safety of the people working at the mine lease area should be given, which would also include measure for treatment of bite of poisonous reptile/insect like snake.
48. Periodical and Annual medical checkup of workers as per Mines Act and they should be covered under ESI as per rule.

Specific Conditions:

1. Validity period of this EC is 5 years from the date of issue as the LoI has been issued for a period of 5 years or co-terminus with the validity of current mine plan or current lease period whichever is earlier. After this period the EC will become null and void.
2. In the absence of replenishment study, in compliance of Hon'ble NGT Order dated 06.05.2022 initially the EC will be operational till 31.12.2022. Permissible quantity and area shall be strictly limited to quantity and area mentioned in LoI or mining plan, whichever is lesser, and maximum mineable depth will be limited to as approved in the mining plan.
3. For subsequent years, Project Proponent shall submit fresh annual replenishment study to SEIAA, UP for amendment in EC for mineable quantity and maximum permissible depth for mining based on scientific findings of replenishment study. Such study shall be placed before SEAC for appraisal for next three years to assess rate of deposition and accordingly, mineable production capacity and depth can be prescribed based on trends analysis, provided it is found scientifically satisfactory by the SEAC. The placing of the study report SEAC is mandatory for initial three years.
4. Directions/suggestions given during public hearing and commitment made by the project proponent should be strictly complied.
5. A certificate from Forest Department shall be obtained that no forest land is involved in mining or as a route and if forest land is involved the project proponent shall obtain forest clearance and permission of Central and State Government as per the provisions of Forest (conservation) Act, 1980 and submit before the start of work.
6. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora fauna etc.
7. If the proposed project is situated in notified area of ground water extraction, where creation of new wells for ground water extraction is not allowed, requirement of fresh water shall be met from alternate water sources other than ground water or legally valid source and permission from the competent authority shall be obtained to use it.
8. Project Proponent should submit action plan for carrying out plantation at least @1,000 plants / ha of lease area. In this case, PP should prepare a plan, duly approved either by Forest Department or Horticulture Department, for planting at least 24,000 plants, either on government land or community land, within a periphery of 5 km from the boundary of the lease area along with provision for maintenance for 5 years. Survival of plants should not be less than the survival rate notified by Uttar Pradesh Forest Department otherwise it will be treated as violation of EC condition.
9. In consultation with District Environment Authority or an Authority nominated by concerned DM, project proponent will prepared a conservation and management plan for rejuvenation and management of water bodies having total surface area of more than 120 ha. Funds for the same will be kept in a separate bank account and six monthly compliance status will be presented by project proponent before the nominated authority in the District.
10. Department of Geology and Mines, Government of Uttar Pradesh and / or concerned district administration, before releasing the security deposit to Project Proponent will ensure that Project Proponent has fully complied with the EC conditions. Non-compliance, if any, should be reported to UPSPCB for appropriate legal action and recovery of compensation.
11. Any application for transfer of this EC, during its validity period unless it is cancelled by a competent authority, has to be necessarily accompanied with status of compliance of EC conditions duly certified by IRO, MoEFCC, GoI, Lucknow.
12. If the air quality deteriorates due to mining, then District Administration & Directorate of Mining should ensure that mining be stopped immediately. Adequate measures be taken for restoring air quality and mining should commence only when air quality attains the prescribed standards.
13. In compliance of Hon'ble NGT Order dated 06.05.2022, for subsequent years, Project Proponent shall submit fresh annual replenishment study to SEIAA, UP for amendment in EC for mineable quantity and maximum permissible depth for mining based on scientific findings of replenishment study. Such

study shall be placed before SEAC for appraisal for next three years to assess rate of deposition and accordingly, mineable production capacity and depth can be prescribed based on trends analysis, provided it is found scientifically satisfactory by the SEAC. The placing of the study report SEAC is mandatory for initial three years.

14. NOC from Irrigation Department/ Concerning Authority regarding river bed mining to be obtained before start of mining activity.
15. The project proponent shall install solar light in their site office.
16. During the submission of 6 monthly compliance reports, the project proponent should make sure that the periodically taken site photographs should also be annexed along with the compliance report.
17. Preference should be given to indigenous local species as per the consultation of the local district Forest Officer.
18. Link Road from the quarry site to the main road shall be constructed as an all-weather road with blacktopping and maintained by the project proponent.
19. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored. Suitable measures shall be taken for proper maintenance of vehicles used in a quarry operation and transportation.
20. The project proponent should explore the possibilities of rainwater harvesting.
21. Agreement/ Consent between project proponent and competent authority/ landowner for haulage road from lease site to link road.
22. Latest technology (water sprinklers/ tankers) to be adopted for mitigating dust at source points in lease area and haulage road during operational activity/vehicular movement.
23. As per the proposed plan, plantation with area specific plant species, number of plants to be planted.
24. Water requirement details along with source of water and the permission/ agreement with the concerning authority/ water supplying agencies to be submitted.
25. The Environmental clearance will be co-terminus with the mining lease period/mining plan whichever is less.
26. At the time of operation, project proponent will comply with all the guidelines issued by Government of India/State Govt./District Administration related to Covid-19.
27. Environment management in according to environmental status and impact of the project.
28. During the school opening and closing time transportation of minerals will be restricted.
29. Selection of plants for green belt should be on the basis of pollution removal index. Project proponent should ensure survival of tree saplings. Mortality should be replaced from time to time.
30. No mining activity should be carried out in-stream channel as per SSMMG, 2016.
31. Pakkamotorable haul road to be maintained by the project proponent.
32. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.
33. Permission from the competent authority regarding evacuation route should be taken.
34. One month monitoring report of the area for air quality, water quality, Noise level. Besides flora & fauna should be examined twice a week and be submitted within 45 days for a record.
35. Provision for cylinder to workers should be made for cooking.
36. The capacity of trucks/tractor for loading purpose will be in tonnes as per Transport Department applicable norms and standard fixed by the Government.
37. Approach road kaccha is to be made motarable and tree saplings to be planted on both sides of the road. Width of the haul road shall be more than 6 meter.
38. Indigenous plants should be planted according to CPCB guidelines and in consultation with local Divisional Forest Officer.
39. The project proponent shall in 2 years conduct detailed replenishment study duly authenticated by a QCI-NABET accredited consultant, and the District Mines Officer.
40. Provision for two toilets and hand pumps should be made at mining site.
41. Drinking water for workers would be provided by tankers.

42. Mining should be done by Bar scalping methods extraction (typically 0.3 -0.6 m or 1 - 2 ft) as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
43. A buffer/safe zone shall be maintained from the habitation as per mining guidelines.
44. Corporate Environmental Responsibility (CER) plan shall be prepared by the project proponent and the details of the various heads of expenditure to be submitted as per the guidelines provided in the recent CER notification No. 22-65/2017-IA.III dated 01/05/2018.
45. Health/Insurance card, Medical claim, regular health check-up camps, facilities shall be provided to the regular/temporary/Contractual or any base workers. Copy of receipt shall be produced to the Directorate of Environment along with the compliance report.
46. Measure for conservation of water through rainwater harvesting and cleaning and maintenance of natural surface water bodies of the nearby areas may be considered as one of the activity in CER.
47. The excavated mining material should be carried and transported in such a way that no obstruction to the free flow of water takes place. Suitable measure should be taken and details to be provided to concern Department.
48. Submit annual replenishment report certified by an authorized agency. In case the replenishment is lower than the approved rate of production, then the mining activity / production levels shall be decreased / stopped accordingly till the replenishment is completed.
49. The project proponent shall ensure that if the project area falls within the eco-sensitive zone of National park/ Sanctuary prior permission of statuary committee of National board for wild life under the provision of Wildlife (Protection) Act, 1972 shall be obtained before commencement of work.
50. If in future this lease area becomes part of cluster of equal to or more than 05 ha. then additional conditions based on the EIA shall be imposed. The lease holder shall mandatorily follow cluster conditions otherwise it will amount to violation of E.C. conditions. If the certificate related to cluster provided by the competent authority is found false or incorrect then punitive actions as per law shall be initiated against the authority issuing the cluster certificate.
51. Project falling within 10 KM area of Wild Life Sanctuary is to obtain a clearance from National Board Wild Life (NBWL) even if the eco-sensitive zone is not earmarked.
52. To avoid ponding effect and adverse environmental conditions for sand mining in area, progressive mining should be done as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
53. In case it has been found that the E.C. obtained by providing incorrect information, submitting that the distance between the two adjoining mines is greater than 500mt. and area is less than 05 ha, but factually the distance is less than 500 mt and the mine is located in cluster of area equal or more than 05 ha, the E.C issued will stand revoked.
54. The project proponent shall in 2 years conduct detailed replenishment study duly authenticated by a QCI-NABET accredited consultant, and the District Mines Officer which shall form the basis for midterm review of conditions of Environmental Clearance.
55. The mining work will be open-cast and manual/semi mechanized (subject to order of Hon'ble NGT/Hon'ble Courts (s)). Heavy machine such as excavator, scooper etc. should not be employed for mining purpose. No drilling/blasting should be involved at any stage.
56. It shall be ensured that there shall be no mining of any type within 03 m or 10% of the width whichever is less, shall be left on both the banks of precise area to control and avoid erosion of river bank. The mining is confined to extraction of sand/moram from the river bank only.
57. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bank material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime of the surrounding area shall not be affected.
58. The project proponent shall adhere to mining in conformity to plan submitted for the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard clearly showing the no work zone in the mine lease i.e. the distance from the bank of river to be left un-worked (Non mining area), distance from the bridges etc. It shall be ensured that no mining shall be carried out during the monsoon season.
59. The project proponent shall ensure that wherever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.

60. The project proponent will provide personal protective equipment (PPE) as required, also provid adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained. For the purpose, schedule of health examination of the workers should be drawn and followed accordingly.
61. The critical parameters such as PM10, PM2.5, SO2 and NOx in the ambient air within the impact zone shall be monitored periodically. Further, quality of discharged water if any shall also be monitored [(TDS, DO, pH, Fecal Coliform and Total Suspended Solids (TSS)].
62. Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. Extensive water sprinkling shall be carried out on haul roads.
63. It should be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.
64. The extended mining scheme will be submitted by the proponent before expiry of present mining plan.
65. Four ambient air quality-monitoring stations should be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring PM10, PM2.5, SO2 and NOx. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the State Pollution Control Board.
66. Common road for transportation of mineral is to be maintained collectively. Total cost will be shared/worked out on the basis of lease area among users.
67. Proponent will provide adequate sanitary facility in the form of mobile toilets to the labours engaged for the project work.
68. Solid waste material viz., gutkhapouchs, plastic bags, glasses etc. to be generated during project activity will be separately storage in bins and managed as per Solid Waste Management rules.
69. Natural/customary paths used by villagers should not be obstructed at any time by the activities proposed under the project.
70. Digital processing of the entire lease area in the district using remote sensing technique should be done regularly once in three years for monitoring the change of river course by Directorate of Geology and Mining, Govt. of Uttar Pradesh. The record of such study to be maintained and report be submitted to Integrated Regional Office, MoEF&CC, GoI, Lucknow, SEIAA, U.P. and UPPCB.
71. The project authorities shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at web site of the SEIAA at http://www.seiaaup.in and a copy of the same shall be forwarded to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, GoI, Lucknow, CPCB, State PCB.
72. The MoEF&CC/SEIAA or any other competent authority may alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
73. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
74. Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 11 of the National Environment Appellate Authority Act, 1997.
75. Waste water from potable use be collected and reused for sprinkling.
76. A width of not less than 50 meter or 10% width of river can be restricted for mining activities from river bank. A condition can be imposed that mining will be done from river activities from river bank.

You shall also ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem

to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this clearance shall automatically deem to be cancelled.

Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

The above stipulated conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along-with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issuance of this clearance. The SEIAA/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of SEIAA/MoEF. SEIAA may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provisions of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14/09/2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

Copy, through email, for information and necessary action to --

1. **The Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Lucknow (email -- soenvups@rediffmail.com)**
2. **Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, 3rd Floor, Prithvi-Block, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 (email – sudheer.ch@gov.in)**
3. **Deputy Director General of Forests (C), Integ rated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020 (email – rocz.lko-mef@nic.in)**
4. **District Magistrate Jhansi.**
5. **Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board. TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (email – ms@uppcb.com)**
6. **Copy to Web Master for uploading on PARIVESH Portal.**
7. **Copy for Guard File.**

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary, SEIAA

Signature Not Verified
Digitally signed by Member Secretary
Member Secretary
Date: 11/18/2022 5:09:19 PM

832 साभागम 06

Uttar Pradesh Pollution Control Board

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226(

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

173141/UPPCB/Jhansi(UPPCBRO)/CTO/both/JHANSI/2022 Date: 05/03/2023

To,

M/s

VIPIN KUMAR SAXENA

KHAND NO.-01 GATA NO.-1419Kh KHANDA NO.-01, VILLAGE-DHAMNAUD, TEHSIL-GARAUTHA, DISTRICT-JHANSI,284203

Application Id-19117307

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **VIPIN KUMAR SAXENA** located at **KHAND NO.-01 GATA NO.-1419Kh KHANDA NO.-01, VILLAGE-DHAMNAUD, TEHSIL-GARAUTHA, DISTRICT-JHANSI,284203.** subject to the provisions of **the Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA VIPIN KUMAR SAXENA **granted for the period from 05/03/2023 to 31/12/2027** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Sand/Morrum	250000	Cubic Meters/Year

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	1.0 KLD	Septic Tank	Soak Pit

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality.In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Dust emission during manual mining, transportation and loading/unloading of Sand/Morrum.			Particulate Matter	water sprinkling system and Green Belt for controlling dust emission.

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1		Particulate Matter	Ambient Air Standard as per E(P) Act 1986.

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.
8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

1. This consent is valid for production capacity Sand/Morrum- 250000 Cu meter/year, by opencast and manual mining in 24 hectare leased area Gata No. 1419 Kh Khand No.- 01, Village- Dharnnaud, Tehsil- Garautha, District- Jhansi.
2. Mining unit shall comply with the conditions of Environmental Clearance issued by State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) vide EC Identification No. EC22B001UP110182 dated 18.11.2022 and submit its compliance report to UPPCB.
3. If the lease agreement expires prior to 31-12-2027, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of mining lease.
4. Mining shall be done as per EC issued by SEIAA and directions given by Mining Department/District Administration.
5. The unit shall submit the latest copy of Audited Balance Sheet/C.A. Certificate (Fixed Assets+ Current Assets - Current Liabilities) for verification of the Consent fee payable by the industry within 15 days. In case CTO fee dues then it shall be submitted to the Board immediately.
6. Unit shall develop and maintain green belt as per the conditions of Environmental Clearance.
7. Unit shall not withdrawal ground water for any industrial activity without obtaining necessary permission from UPGWA.
8. The domestic effluent shall be treated through septic tank/soak pit or provide mobile toilet facility. Industry shall maintain ZLD.
9. Unit shall make water sprinkling arrangement through Tankers for dust suppression at different sources of dust emission during mining, transportation, loading and unloading of Sand/Morrum.
10. Unit should operate and maintain installed water sprinkler system effectively and continuously to achieve the standards prescribed under E(P) Rules, 1986.
11. Unit shall submit Ambient air monitoring reports of NABL accredited laboratory on quarterly basis to the Board.
12. All trucks, tractors used in transportation of Sand/Morrum shall be covered by canvas sheet to prevent dust emission.
13. Water will be sprayed after loading activity (if Sand/Morrum collected could be dry condition)
14. The dust suppression measures like water spraying will be done on the haul roads and working areas.
15. Industry should comply with the provisions of Hazardous and Other waste (Management & Trans boundary Movement) Rules 2016.
16. Solid waste should be disposed in such manner, so that no water, air and soil pollution takes place.
17. Industry shall abide by directions given by Hon'ble Court, MoEF&CC, Central Pollution Control Board and UPPCB for protection and safe guard of environment from time to time.
18. Consent fees if revised, shall be payable by industry from the date of its applicability.
19. Industry shall comply with the relevant provisions of Environmental Laws.
20. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order.

RAJENDRA SINGH

Digitally signed by RAJENDRA SINGH
Date: 2023.03.06 09:16:18 +05'30'

Chief Environmental Officer (circle-2)

Copy to:

Regional Officer, UPPCB, Jhansi with direction to send the compliance report of CTO conditions on quarterly basis.

836

RAJENDRA SINGH

Digitally signed by RAJENDRA SINGH
Date: 2023.03.06 09:16:28 +05'30'

Chief Environmental Officer (circle-2)

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :25/01/2023 To 24/01/2028

Ref No. - **172410/UPPCB/Jhansi(UPPCBRO)/CTE/JHANSI/2022** **Dated:- 28/01/2023**

To ,

Shri VIPIN KUMAR SAXENA
M/s VIPIN KUMAR SAXENA
KHAND NO.-01 GATA NO.-1419Kh KHANDA NO.-01, VILLAGE-DHAMNAUD, TEHSIL-GARAUTHA, DISTRICT-JHANSI,284203
JHANSI

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Polution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 18988000 dated - 15/12/2022. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates :

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	**Raw Material Unit Name**	**Raw Material Quantity**
SAND MORRUM	Cubic Meters/Year	250000

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	**Product Quantity**
SAND MORRUM MINING (CUBIC METER/ANNUM)	250000

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	**Unit Name**	**Licence Product Capacity**	**Install Product Capacity**
NA	Cubic Meters/Year	0	0

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	**Name of Source**	**Quantity (KL/D)**
River	RIVER	16.0

3. Quantity of effluent (In KLD) :

कार्यालय जिलाधिकारी,झॉसी।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः– 58 / 30एम0एम0सी0 / 2024–25 दिनांक 29/04/2024

आदेश

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन–लखनऊ द्वारा निर्गत शासादेश संख्या–1659 / 86–2023 दिनांकः 17.05.2023 के बिन्दु संख्या–6 में जनपद के विधिमान्य खनन क्षेत्र एवं नये चिन्हित खनन क्षेत्रों को Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 तथा Enforcement & Monitoring Guidleines For Sand Mining 2020 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) Updation / Modification कर तैयार किये जाने हेतु जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी / प्रभारी अधिकारी खनिज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें सिंचाई, वन तथा राजस्व विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी / खान निरीक्षक उक्त समिति के संयोजक सदस्य के रूप में नामित किये जाने के दिशा–निर्देश दिये गये। उक्त के कम में निदेशालय के पत्र संख्या–2182 / एम0–228 / खनन नीति–2017 डी0एस0आर0 दिनांकः 12.02.2024 द्वारा जनपदों के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक दिनांकः 02.02.2024 में लिये गये निर्णय एवं तैयार की गयी Standard Operating Procedure (SOP) के अनुसार तैयार कराकर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त पत्र में संलग्नक Standard Operating Procedure (SOP) के पृष्ठ संख्या–3 में उल्लिखित तालिका के कमांक संख्या–1 जनपद में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु Sub Divisional Committee (SDC) में उपजिलाधिकारी, अधिशाषी अभियंता सिचांई विभाग,स्टेट पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, प्रभागीय वनाधिकारी एवं भू–वैज्ञानिक / खान अधिकारी का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद में विधिमान्य खनन क्षेत्र एवं नये चिन्हित खनन क्षेत्रों के सम्बन्ध जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु शासनादेश दिनांकः 17.05.2023 के बिन्दु संख्या–6 में प्रभारी अधिकारी (खनिज) की अध्यक्षता मे उल्लिखित समिति एवं निदेशालय के पत्र दिनांकः 12.02.2024 की संलग्नक–(एस0ओ0पी0) में Sub Divisional Committee (SDC) के सदस्यो को समाहित करते हुए निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:–

1.	प्रभारी अधिकारी (खनिज)	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी	सदस्य
3.	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
4.	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 पदूषण नियंत्रण बोर्ड–झॉसी	सदस्य
5.	क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय–झॉसी।	सदस्य
6.	अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग–झॉसी	सदस्य
7.	ज्येष्ठ खान अधिकारी–झॉसी	सदस्य
8.	खान निरीक्षक–झॉसी	सदस्य
9.	सर्वेक्षक,खनिज विभाग–झॉसी	सदस्य

अतः उपरोक्त गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि जनपद–झॉसी में विधिमान्य उपखनिज के खनन के क्षेत्रों एवं नवीन खनन क्षेत्रों को Standard Operating Procedure (SOP) के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) को तैयार कराने के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। ताकि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) को समयान्तर्गत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

जिलाधिकारी,
झॉसी।

पत्रांक व तद्दिनांकः
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,उ0प्र0, लखनऊ।
2. समिति के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी,
झॉसी।